



डजिटल अर्थव्यवस्था

प्रलिस के लयः

डजिटल क्षेत्र में भारत सरकार की पहल, [G20](#)

मेन्स के लयः

डजिटल अर्थव्यवस्था- महत्त्वपूरण प्रभाव, चुनौतय़ीं, आगे की राह

चर्चा में क्य़ों?

इलेक्ट्रॉनक्स और सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय (MeitY) ने 17 से 19 अप्रैल 2023 तक हैदराबाद में [G20](#) डजिटल इकोनॉमी वर्कगि ग्रुप (DEWG) की दूसरी बैठक का आयोजन कया ।

- G20 DEWG की पहली बैठक भवय़ीय में उत्पादक और सार्थक वचार-वमिर्श पर बल देने के साथ फरवरी 2023 में आयोजति की गई थी ।

बैठक के प्रमुख बडुः

- **डजिटल अर्थव्यवस्था का महत्त्व और बढ़ता दायरा:** वर्तमान में डजिटल अर्थव्यवस्था प्रमुखता प्राप्त करने के साथ वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतवधिय़ों के वभिन्न पहलुओं को प्रभावति कर रही है । इससे संकेत मलिता है क डजिटल अर्थव्यवस्था अब कसी वशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमति नहीं है बल्क अर्थव्यवस्था के हर पहलू तक वसितारति हो रही है ।
- **डजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में भारत की मान्यता:** डजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्त्व के बारे में भारत की जागरूकता, इसकी G20 अध्यक्षता और इससे जुड़े अवसरों और चुनौतय़ीं के क्रम में आयोजति की जाने वाली बैठकों से प्रदर्शति होती है ।
- **वनरिमाण पर डजिटल अर्थव्यवस्था का प्रभाव:** ऐसा कहा जाता है क पारंपरिक वनरिमाण क्षेत्र भी डजिटल अर्थव्यवस्था से प्रभावति और परिवर्तति हो रहे हैं । इसका तात्पर्य यह है क डजिटल प्रौद्योगकिय़ों और प्रक्रय़ीओं के एकीकरण से [वनरिमाण](#) गतवधिय़ों को बढ़ावा मलिने के साथ इनमें सुधार हो रहा है ।
- **इसके तीन महत्त्वपूरण पहलू:**
 - मजबूत डजिटल बुनयादी ढाँचे के विकास के महत्त्व को समझना ।
 - डजिटल प्रणाली और डेटा की सुरक्षा सुनशिचति करने के लयि [साइबर सुरक्षा](#) उपायों को महत्त्व देना ।
 - [कुशल कार्यबल](#) के विकास के क्रम में प्रशकषण पर बल देना जसिसे डजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत की स्थति मजबूत हो सके ।

डजिटल क्षेत्र में भारत सरकार की पहल:

- **प्रमुख डजिटल पहल:** भारत सरकार ने डजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं । जैसे:
 - **भारतनेट परयोजना:** इसका लक्ष्य वर्ष 2023 तक भारत के सभी गाँवों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है ।
 - **स्टार्टअप इंडया कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य उद्यमति को बढ़ावा देना और स्टार्टअप के लयि अनुकूल पारस्थितिकी तंत्र बनाना है ।
 - **डजिटल साक्षरता अभयान (DISHA) कार्यक्रम:** इसे वर्ष 2016 में शुरू कया गया था और इसका लक्ष्य प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को डजिटल रूप से साक्षर बनाना है ।
- **ई-रुपया और सशरत हस्तांतरण:** [ई-रुपया](#) और सशरत हस्तांतरण की हालयिा प्रवृत्ति, व्यवसाय और शासन दोनों के लयि नरिणायक हो सकती है ।
 - **MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)** और व्यापार पारस्थितिकी तंत्र के अन्य क्षेत्रों में सशरत हस्तांतरण के लयि डजिटल

वाउचर या ई-रुपया के उपयोग से अर्थव्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

- **वित्तीय समावेशन:** विश्व भर में लगभग 75% वयस्कों के पास औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच है। डिजिटल रूप से बचत करने, खर्च करने और उधार लेने की क्षमता का भारत जैसे संसाधन संपन्न देश के संदर्भ में व्यापक आर्थिक प्रभाव है, क्योंकि इससे नगिमें और सरकारों के घाटे को पूरा करने के लिये घरेलू वित्तीय बचत और वदेशी बचत को प्रोत्साहन मल्लिगा।
- **मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया:** इन कार्यक्रमों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में वनिर्माण को बढ़ावा देना है जबकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अपनाने को बढ़ावा देना है।
 - ये दोनों कार्यक्रम एक-दूसरे के पूरक हैं। मेक इन इंडिया के तहत डिजिटल उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है जबकि डिजिटल इंडिया, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण प्रभाव:

- **जनसांख्यिकीय लाभ:** डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता को दोहन में जनसांख्यिकीय लाभांश भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिये भारत में अंग्रेजी में दक्ष और प्रौद्योगिकी को पसंद करने वाली एक बड़ी आबादी ने **UPI (यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)** और **DBT (डायरेक्ट बेंफिट ट्रांसफर)** जैसी डिजिटल प्रणालियों को अपनाने में रूचा दिखाई है जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
 - स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने से इनकी पहुँच और समावेशिता बढ़ सकती है, जिससे काफी अधिक लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था से लाभान्वित हो सकेंगे।
- **वभिन्न सेवाओं का वसितार:** डिजिटल अर्थव्यवस्था से स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सेवा क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन करने तथा उसे वसितारित करने के अवसर प्राप्त होते हैं। G20 सदस्यों सहित कई विकसित देश **सेवा क्षेत्र** को उदार बनाने के क्रम में उन्मुख रहे हैं।
 - डिजिटल अर्थव्यवस्था से **चिकित्सा सेवाओं और शैक्षिक सेवाओं जैसी सेवाओं के वसितार को सक्रम** किया जा सकता है।
 - उदाहरण के लिये **UMANG मोबाइल ऐप** भारत सरकार का एक एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी-चैनल, बहुभाषी, बहु-सेवा मोबाइल ऐप है।
- **सेवाओं का सीमा पारीय वसितार:** डिजिटल अर्थव्यवस्था में सीमा पार सेवाओं के वसितार की क्षमता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, योग्य पेशेवर भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए वशि्व स्तर पर अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। इसमें सेवा क्षेत्र को नया आकार देने तथा सेवा प्रदाताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता शामिल है।
 - सेवा क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी क्षमता को सार्थक करने में जी 20 महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने और इससे संबंधित बाधाओं को दूर करने से कुशल वैश्विक बाजार का निर्माण होगा।
- **अन्य महत्त्वपूर्ण प्रभाव:** डिजिटल अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे स्थानीय स्तर पर नौकरियाँ सृजित होने एवं उत्पादकता और व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ अधिक लोगों की सेवाओं और अवसरों तक पहुँच सक्रम हुई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास से नए बिजनेस मॉडल और उद्योगों का भी उदय हुआ है जैसे **ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान** आदी।

चुनौतियाँ:

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियों को हल करना:** डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जनि पर ध्यान देने की आवश्यकता है:
 - **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर**
 - **डिजिटल कौशल**
 - **साइबर सुरक्षा**।
- इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। भारत ने एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है और डिजिटल कौशल पहल में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है लेकिन इससे संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** में महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को एक ऐसे कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अक्षम होने या नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं लोक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
 - **सुरक्षा:** वर्तमान में डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं (खासकर वित्तीय क्षेत्र में)। ऐसे में डिजिटल क्षेत्र में लेनदेन की तीव्र गति चिंताजनक हो सकती है जिससे होने वाली त्रुटियों को सुधारना या धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का समाधान करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
 - **कुशल जनशक्ती का महत्त्व:** डिजिटल क्षेत्र में कुशल कार्यबल के विकास की उपेक्षा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की पूरी क्षमता में बाधा बन सकती है। डिजिटल बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाने के लिये डिजिटल रूप से साक्षर लोगों को तैयार करने के क्रम में शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है।
 - **तकनीकी पछिडापन:** इससे संबंधित प्रमुख चुनौतियों में से एक लोगों के बीच डिजिटल अंतराल का होना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के पास अभी भी डिजिटल सेवाओं तक पहुँच नहीं है। डिजिटल अर्थव्यवस्था से असमानता को बढ़ावा मिलने के साथ कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ हुआ है।

आगे की राह:

- **लेन-देन संबंधी सुरक्षा को मज़बूत करना:** इन चुनौतियों को कम करने के लिये इस दशा में प्रभावी जाँच और संतुलन करना महत्त्वपूर्ण है। इसका एक सकारात्मक उदाहरण भारत में **वन-टाइम पासवर्ड (OTPs)** का उपयोग होना है जिससे उपयोगकर्ताओं को अपने लेनदेन को सत्यापित करने की सुविधा मिलती है। ऐसे उपाय सुरक्षा बढ़ाने में मदद करते हैं और उपयोगकर्ताओं को अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- **डिजिटल युग में वित्तीय समावेशन और सुरक्षा:** **JAM ट्रिनिटी (जन धन योजना, आधार, मोबाइल)** जैसी पहलों द्वारा होने वाली कनेक्टिविटी प्रगति से वित्तीय समावेशन में सुधार हुआ है, जिससे लोगों को डिजिटल सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हुई है। **इंटरनेट बैंकिंग** और एटीएम लेनदेन ने भी बैंकिंग को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है।
 - हालाँकि इनमें से प्रत्येक प्रगति से संबंधित जोखिम वदियमान हैं, जिससे यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि लेनदेन सुरक्षित और सतर्क तरीके से हों।
- **लेनदेन संबंधी सुरक्षा को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण:** इन चुनौतियों का समाधान करने के लिये विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं। ओटीपी के अलावा, कुछ अनुप्रयोगों में कीबोर्ड के पैटर्न में संख्यात्मक कीपैड लेआउट परिवर्तन तथा उपयोगकर्ताओं के लिये अलर्ट प्रणाली स्थापित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त जब लेनदेन एक नश्चित सीमा से अधिक हो जाता है या सामान्य पैटर्न से वचलित होता है तो कॉल सेंटर के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है।
- **साइबर सुरक्षा बढ़ाना:** कुल मिलाकर मुख्य बल इस बात पर होना चाहिये कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से अंतिम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होने के साथ उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाए। सतर्कता, सक्रिय उपाय और धन के लेन-देन से संबंधित चुनौतियों का नरितर मूल्यांकन करना, विश्व भर में एक सुरक्षित डिजिटल लेनदेन वातावरण स्थापित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कौशल:** डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कौशल आपस में संबंधित हैं। इन्हें एक ही सिके के दो पहलू के रूप में देखा जाता है जिसके तहत सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के साथ-साथ इसका उपयोग करने और इससे लाभ उठाने में सक्षम कुशल कार्यबल के विकास पर बल दिया जाता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: नमिनलखित कथनों पर वचार कीजयि: (2018)

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरकता या अधवास के प्रमाण के रूप में कथि जा सकता है।
2. एक बार जारी करने के पश्चात इसे नरिगत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को नषिक्रयि या लुप्त नहीं कर सकता है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न. जनसांख्यिकीय लाभांश से पूर्ण रूप से लाभान्वति होने के लयि भारत को क्या करना चाहयि? (2013)

- (a) कौशल वकिस को बढ़ावा देना
- (b) अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुरु करना
- (c) शशु मृत्यु दर को कम करना
- (d) उच्च शकिसा का नजीकरण करना

उत्तर: (a)